

प्रधानमंत्री जनधन योजना

- लॉन्च किया गया: 15 अगस्त 2014
- वित्त मंत्रालय के नेतृत्व में
- उद्देश्य: वित्तीय समावेशन
- उम्र: 18 और 59
- रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा के साथ बुनियादी बचत बैंक खाते। प्रत्येक पात्र वयस्क को 10,000/- रु
- 19 जुलाई, 2024 तक
- खाते और जमा: 52.81 करोड़ जन-धन खाते जिनमें जमा राशि रु. 2,30,792 करोड़।
- महिला खाते: 29.37 करोड़ खाते (55.6%) महिलाओं के हैं।
- ग्रामीण और अर्ध-शहरी कवरेज: 35.15 करोड़ खाते (66.6%) ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं।
- प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेबीवाई): 20.48 करोड़ नामांकन रुपये का जीवन बीमा कवर प्रदान करते हैं। किसी भी कारण से मृत्यु होने पर 2 लाख रु.
- प्रधान मंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई): 45.08 करोड़ नामांकन रुपये के आकस्मिक कवर की पेशकश करते हैं। 2 लाख (मृत्यु या स्थायी पूर्ण विकलांगता) और रु. 1 लाख (स्थायी आंशिक विकलांगता)।
- अटल पेंशन योजना (एपीवाई): 6.71 करोड़ नामांकन पात्र ग्राहकों को मासिक पेंशन प्रदान करते हैं।

मिलियन डिज़ाइनर, बिलियन ड्रीम्स

- घोषित: दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM)
- इसका उद्देश्य पूरे भारत में व्यक्तियों को सशक्त बनाना है
- DAY-NRLM के सहयोग से LEAP द्वारा नेतृत्व किया गया।
- मॉडल कौशल ऋण योजना
- मंत्रालय: कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
- उद्देश्य: वित्तीय बाधाओं को दूर करना
- रुपये तक के संपार्श्विक-मुक्त ऋण। 7.5 लाख (पहले, यह ₹1.5 लाख था)।
- गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी), एनबीएफसी-माइक्रो फाइनेंस संस्थानों (एनबीएफसी-एमएफआई) और छोटे वित्त बैंकों को शामिल करने के लिए पात्रता का विस्तार करता है।

स्मार्ट सिटी मिशन

- लॉन्च किया गया: 2015
- 31 मार्च 2025 तक कार्यकाल का विस्तार
- केंद्र सरकार ने पांच वर्षों में 48,000 करोड़ रुपये का पर्याप्त योगदान देने का वादा किया, यानी प्रति वर्ष प्रति शहर औसतन 100 करोड़ रुपये।
- तीन प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना:
- मुख्य बुनियादी ढांचा उपलब्ध कराना
- स्वच्छ एवं टिकाऊ वातावरण बनाना
- नागरिकों के लिए जीवन की सभ्य गुणवत्ता सुनिश्चित करना
- इस परिवर्तनकारी यात्रा का हिस्सा बनने के लिए 100 शहरों को चुना गया।
- 13 स्मार्ट शहरों के साथ उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, इसके बाद 12 स्मार्ट शहरों के साथ तमिलनाडु और 10 स्मार्ट शहरों के साथ महाराष्ट्र है।

PM Gati Shakti Scheme

- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए मास्टर प्लान
- लॉन्च किया गया: अक्टूबर 2021
- बुनियादी ढांचा कनेक्टिविटी परियोजनाओं की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए अनिवार्य रूप से एक डिजिटल मंच।

- पीएम गति शक्ति मोटे तौर पर 7 इंजनों, सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित है।

Safai Apnao, Bimaari Bhagao Initiative

- आवास और शहरी कार्य मंत्रालय (MoHUA)
- स्वच्छ भारत मिशन-शहरी 2.0 के तहत लॉन्च किया गया
- अवधि: 1 जुलाई से 31 अगस्त 2024 तक
- उद्देश्य: मानसून के मौसम के दौरान बढ़ती स्वच्छता और स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) को मजबूत करना।
- यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के 'स्टॉप डायरिया अभियान' के अनुरूप है, जिसमें व्यापक हस्तक्षेप और अंतर-विभागीय सहयोग पर जोर दिया गया है।

व्यवहार्यता गैप फंडिंग (वीजीएफ) योजना

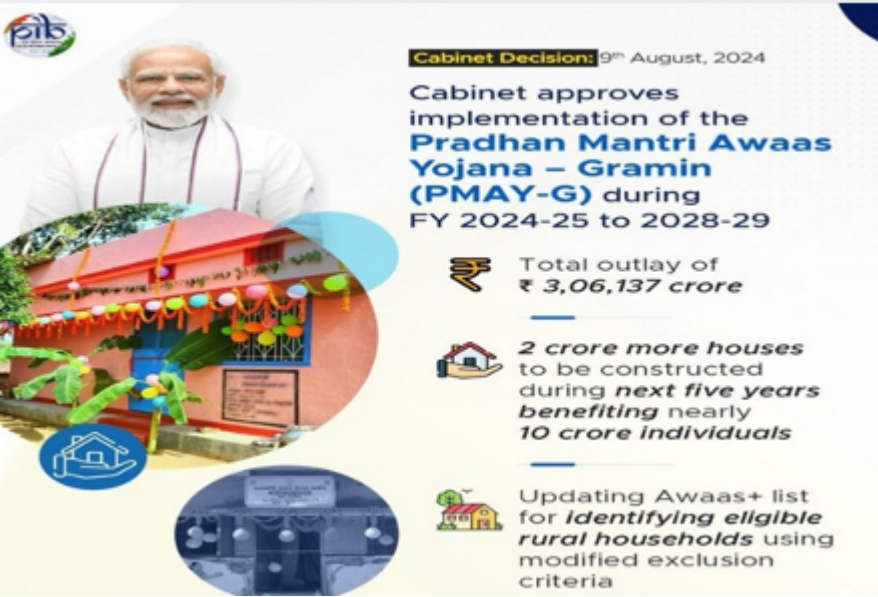
- अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं का कार्यान्वयन
- इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹7,453 करोड़ है।
- वीजीएफ योजना में 1 गीगावॉट अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना और कमीशनिंग के लिए आवंटित ₹6,853 करोड़ शामिल हैं, जो गुजरात और तमिलनाडु के तटों पर 500 मेगावाट की दो परियोजनाओं में विभाजित हैं।
- इसके अतिरिक्त, इन परियोजनाओं के लिए रसद आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए दो बंदरगाहों के उन्नयन के लिए ₹600 करोड़ निर्धारित किए गए हैं।
- नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय को नोडल मंत्रालय बनाया गया है।

Mission Karmayogi

- लॉन्च किया गया: 2020
- उद्देश्य: एक सक्षम और भविष्य के लिए तैयार सिविल सेवा बनाना जो नागरिकों की जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील हो।

Pradhan Mantri Awas Yojana (PMAY)

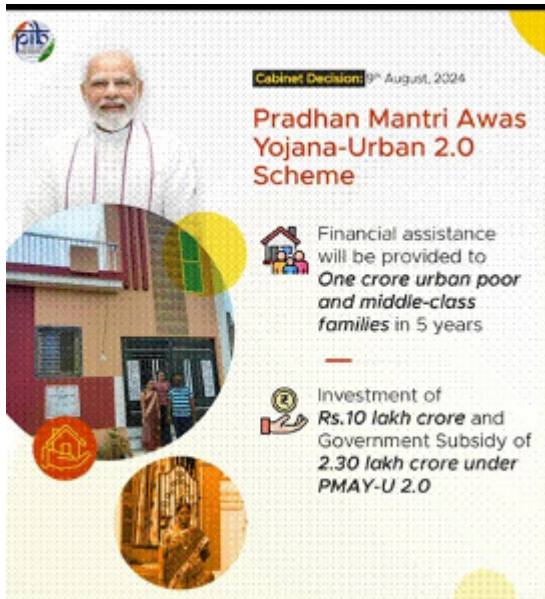
- उद्देश्य: वर्ष 2022 तक सभी के लिए आवास
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (MoHUA) द्वारा कार्यान्वित
- 25 जून 2015 को लॉन्च किया गया



Cabinet Decision: 9th August, 2024

Cabinet approves implementation of the **Pradhan Mantri Awas Yojana – Gramin (PMAY-G)** during FY 2024-25 to 2028-29

-  Total outlay of ₹ 3,06,137 crore
-  2 crore more houses to be constructed during next five years benefiting nearly 10 crore individuals
-  Updating Awas+ list for identifying eligible rural households using modified exclusion criteria



- इंडब्ल्यूएस परिवार: वार्षिक आय ₹3 लाख तक।
- एलआईजी परिवार: वार्षिक आय ₹3 लाख से ₹6 लाख तक।
- एमआईजी परिवार: वार्षिक आय ₹6 लाख से ₹9 लाख तक।

एमजीएनआरईजीएस

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना
- बजट 2024-25: मनरेगा के लिए आवंटन 86,000 करोड़ रुपये पर स्थिर है।
- हरियाणा में अकुशल श्रमिकों के लिए प्रति दिन 374 रुपये की उच्चतम मजदूरी दर है।
- इसके विपरीत, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में मजदूरी दर सबसे कम 234 रुपये है।

PM-SURAJ

- Pradhan Mantri Samajik Utthan and Rozgar Adharit Jankalyan' (PM-SURAJ)
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा आयोजित।
- उद्देश्य: ऋण सहायता बढ़ाना और वंचित समुदायों के एक लाख उद्यमियों को सशक्त बनाना।

NAMASTE Scheme

- यंत्रीकृत स्वच्छता पारिस्थितिकी तंत्र के लिए राष्ट्रीय कार्यवाई
- सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय और आवास और शहरी मामले मंत्रालय की संयुक्त पहल
- NSKFDC द्वारा तीन वर्षों के लिए कार्यान्वित किया गया
- योजना के घटक
 - सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों (एसएसडब्ल्यू) की प्रोफाइलिंग
 - स्वास्थ्य बीमा और व्यावसायिक सुरक्षा प्रशिक्षण
 - पूंजीगत सब्सिडी और उपकरण वितरण
 - आईईसी अभियान और क्षमता निर्माण

पीएम स्वनिधि

- केंद्रीय क्षेत्र योजना
- आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित
- क्रमशः ₹10,000 और ₹20,000 के पहले और दूसरे ऋण के अलावा ₹50,000 तक के तीसरे सावधि ऋण की शुरुआत।
- उद्देश्य:
- कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा के लिए;

- नियमित पुनर्भुगतान को प्रोत्साहित करना; और
- डिजिटल लेनदेन को पुरस्कृत करना
- ऋण की समय पर/जल्दी चुकौती पर, छह मासिक आधार पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण के माध्यम से लाभार्थियों के बैंक खातों में 7% प्रति वर्ष की ब्याज सब्सिडी जमा की जाएगी।

PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana

- छत पर सौर प्रणाली के माध्यम से एक करोड़ घरों को मुफ्त बिजली प्रदान करने का लक्ष्य।
- 75,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का बजट आवंटित.
- नागरिक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली का लाभ उठा सकते हैं।
- पात्रता मानदंड: वार्षिक पारिवारिक आय 1.5 लाख रुपये से अधिक नहीं।

Ek Ped Maa Ke Naam

- लॉन्च किया गया: 5 जून, 2024 को विश्व पर्यावरण दिवस
- लॉन्च किया गया: प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी
- Planting a peepal tree sapling at Buddha Jayanti Park in Delhi.

Viksit Bharat by 2047

- उद्देश्य: 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र में बदलना।
- Viksit Bharat by 2047
- पूर्वोदय योजना:
- शामिल क्षेत्र: झारखंड, बिहार, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश।
- फोकस: बुनियादी ढांचा, मानव संसाधन विकास और आर्थिक अवसर।
- उद्देश्य: पूर्वी क्षेत्र को ग्रोथ इंजन बनाएं।

बजट 2024-25 में योजनाएं

Viksit Bharat by 2047

- परमाणु ऊर्जा विकास:
- पहल: भारत लघु रिएक्टर, भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर स्थापित करने और नई परमाणु प्रौद्योगिकियों को विकसित करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी।

आत्मनिर्भर तिलहन अभियान

- उद्देश्य: तिलहन में आत्मनिर्भरता हासिल करना।
- कवरेज: मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल और सूरजमुखी।
- फोकस क्षेत्र: आधुनिक कृषि तकनीक, उच्च उपज वाली किस्में, मूल्यवर्धन, खरीद, बाजार जुड़ाव और फसल बीमा।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ

- स्कीम ए: पहली बार आने वाले
- लक्ष्य: औपचारिक क्षेत्रों में नए कार्यबल का प्रवेश।
- लाभ: एक महीने का वेतन तीन किस्तों में 15,000 रुपये तक।
- योग्यता: प्रति माह 1 लाख रुपये तक वेतन।
- असर: 210 लाख युवाओं को फायदा।

रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाएँ

- स्कीम बी: विनिर्माण में रोजगार सृजन
- फोकस: विनिर्माण क्षेत्र में पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों से जुड़ा अतिरिक्त रोजगार।
- प्रोत्साहन: रोजगार के पहले चार वर्षों के लिए ईपीएफओ योगदान सहायता।

- प्रभाव: 30 लाख युवाओं और उनके नियोक्ताओं को लाभ।

नया कौशल कार्यक्रम

- उद्देश्य: पांच वर्षों में 20 लाख युवाओं को कौशल प्रदान करना।
- पहल: उद्योग सहयोग से 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करें।
- फोकस: पाठ्यक्रम सामग्री को उद्योग की जरूरतों के साथ संरेखित करें और उभरते क्षेत्रों के लिए नए पाठ्यक्रम पेश करें।

Ministry of Health & Family Welfare	Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Nidhi	Improve healthcare infrastructure and services.
	Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Aarogya Yojana	Provide health insurance coverage to economically vulnerable families.
	National Digital Health Mission	Develop a digital health ecosystem and enhance healthcare delivery through technology.
	Pradhan Mantri Swasthya Suraksha Yojna	Enhance healthcare infrastructure in rural areas.
	Intensified Mission Indradhanush 3.0	Increase immunization coverage among children and pregnant women.

Ministry of Education	STARS Project	Support the strengthening of school education systems.
	Institutions of Eminence Scheme	Upgrade selected higher education institutions to world-class standards.
	Mid-Day Meal	Provide nutritious meals to school children to improve their health and education.
	Swachh Vidyalaya Abhiyan	Ensure the availability of proper sanitation facilities in schools.
	Kala Utsav	Promote and celebrate the cultural diversity of India through arts and crafts.
	Shikshav Parv Initiative	Enhance the quality of education through various reforms and initiatives.

Ministry of Women and Child Development	Pradhan Mantri Matru Vandana Yojna	Provide financial support to pregnant and lactating mothers.
	Poshan Abhiyan	Improve nutritional outcomes for children, pregnant women, and lactating mothers.
	Rashtriya Poshan Maah	Focus on enhancing nutritional awareness and interventions.
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship	Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojna	Provide skill training to youth to enhance employability.

Ministry of Rural Development	Unique Land Parcel Identification Number (ULPIN) Scheme	Provide a unique identification number for land parcels to improve land records.
	National Social Assistance Programme (NSAP)	Provide social assistance to the elderly, widows, and disabled individuals.
	Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Scheme (MGNREGS)	Guarantee employment to rural households and enhance their livelihoods.
	Rashtriya Aajivika Mission	Promote self-employment and livelihood opportunities in rural areas.

Ministry of Housing & Urban Affairs	Global Housing Technology Challenge	Promote innovative housing technologies and solutions.
	Safaimitra Suraksha Challenge	Improve sanitation and safety for sanitation workers.
	PM SVANIDI	Provide street vendors with loans and financial support.
	Climate-Smart City Assessment Framework	Assess and improve climate resilience of urban areas.
	Swachh Sarvekshan 2021	Evaluate and improve urban sanitation and cleanliness.

Ministry of Jal Shakti	Rashtriya Swachhta Kendra	Promote and maintain cleanliness and sanitation practices.
	Grand ICT Challenge	Use information and communication technology for water management.
Ministry of Social Justice & Empowerment	Ambekar Social Innovation & Incubation Mission	Foster social innovation and entrepreneurship for marginalized communities.
Ministry of Finance	Saral Jeevan Bima	Provide simplified life insurance products.

Ministry of Commerce & Industry	One District One Product Scheme	Promote local products and manufacturing in each district.
	PRARAMBH: Startup India International Summit	Facilitate and promote international startup collaborations and investments.
	Merchandise Export From India Scheme	Enhance merchandise exports from India.

Ministry of Textiles	SAMARTH Scheme	Support skill development and employment in the textile sector.
	National Technical Textile Mission	Promote research and development in technical textiles.
Ministry of Ports, Shipping & Waterways	Sagarmala Sea Plane Services	Enhance sea plane connectivity and services.
	National Authority For Recycling of Ships	Promote recycling of ships and sustainable practices.
Ministry of Labor & Employment	Atal Beemit Vyakti Kalyan Yojna	Provide financial support to unemployed individuals.
	Nation Career Service Project	Enhance career services and employment opportunities.

Ministry of Consumer Affairs, Food, and Public Distribution	Bureau of Indian Standards	Develop and enforce quality standards for goods and services.
	Consumer Protection (E-commerce) Rules, 2020	Regulate and protect consumer interests in the e-commerce sector.
Ministry of Statistics & Programme Implementation	MPLADS (Members of Parliament Local Area Development Scheme)	Fund development projects in parliamentary constituencies.

NITI Aayog	Vision 2035	Set long-term development goals and strategies for India.
	NPMPF (National Program and Project Management Policy Framework)	Implement project management frameworks for efficient execution of government projects.
	Aatmanirbhar Bharat ARISE-Atal New India Challenge	Promote innovation and research to drive self-reliance and development.
Minister of Railways, Commerce and Industry, Consumer Affairs and Food and Public Distribution	Startup India Seed Fund Scheme (SISFS)	Provide seed funding to startups and encourage entrepreneurship.